Vol 7 Issue 3 April 2017

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 IMPACT FACTOR : 5.1651(UIF) VOLUME - 7 | ISSUE - 3 | APRIL - 2017

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

छोटे राज्यों का निर्माण विकास का मानक नही (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में)

डॉ. दलीपसिंह
राजनीति विज्ञान विभाग ,
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ,राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी (नैखरी)
पो. ऑ.–जामणीखाल .

सारांशः

मध्य हिमालय में स्थित उत्तराखण्ड राज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं भूगर्भिक संरचना के कारण जहां अतिसंवेदनशील है। वही नेपाल व तिब्बत (चीन) से अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें लगी होने के कारण यह क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय दृष्टि, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अति महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में आर्थिक प्रगति ही किसी क्षेत्र की समृद्धि का परिचायक है और जो देश या क्षेत्र आर्थिक प्रगति की दृष्टि से पिछड़ जाए, उन्हे पिछड़े हुए क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद भी अनुकूल आर्थिक नीतियों एवं विकास योजनाओं के अभाव में उत्तराखण्ड पिछड़े एवं अल्प विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। सरकारों की इन्हीं अव्यवहारिक नीतियों के चलते पहाड़ के लोगों ने अलग राज्य की माँग की थी। लोगों को विश्वास था कि राज्य बनेगा तो पहाड़ के विकास की नीति व्यवहारिक एवं पहाड़ की परिस्थितियों के अनुकूल पहाड़ के हित में होगी। परिणामस्वरूप 9 नवम्बर, 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ, जिसका नाम 1 जनवरी, 2007 को उत्तराखण्ड कर दिया गया। छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क दिया जाता है, कि वर्तमान समय में अनेक राज्य प्रशासकीय दृष्टि से बहुत बड़े हैं, जिसके कारण न तो उनका समुचित प्रबंधन हो पाता है और न ही वह अपने जातीय, सांस्कृतिक समुदायों की आकांक्षायें पूरी करने में सफल हो पाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि छोटे राज्य बना देने मात्र से सभी समस्याओं का (रामबाण) समाधान हो ऐसा भी नही है, बल्कि इसके लिए एक ईमानदार प्रयास एवं वैज्ञानिक आधार पर परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों का निर्धारण है।

प्रस्तुत शोध पत्र "छोटे राज्यों का निर्माण विकास का मानक नही (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में" में विस्तृत चर्चा की गई है।

पृथक राज्यों की माँग :

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद अनुकूल आर्थिक नीतियों एवं विकास योजनाओं के अभाव में उत्तराखण्ड पिछड़ा एवं अल्प विकसित राज्य है। सरकारों की अव्यवहारिक नीतियों एवं बच्चों के भविष्य की चिंता के चलते पहाड़ के लोगों ने अलग राज्य की माँग की थी। लोगों को विश्वास था कि राज्य बनेगा तो पहाड़ के विकास की नीति व्यवहारिक एवं पहाड़ की परिस्थितियों के अनुकूल पहाड़ के हित में होगी। छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क दिया जाता है, कि वर्तमान समय में अनेक राज्य प्रशासकीय दृष्टि से बहुत बड़े हैं। जिसके कारण न तो उनका समुचित प्रबंधन हो पाता है और न ही वह अपने जातीय, सांस्कृतिक समुदायों की आकांक्षायें पूरी करने में सफल हो पाते हैं। जिसके चलते समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों से पृथक राज्यों की माँग उठती रही है। बड़े क्षेत्रफल होने के कारण स्वतंत्रता के बाद भी इन क्षेत्रों में इस प्रकार का असंतुलन पूर्ववत की तरह बरकरार है और कहीं–कहीं तो पहले की अपेक्षा यह असंतुलन और अधिक बढा है। प्रसिद्ध लेखक हरद्वारी लाल लिखते है कि, "छोटे राज्यों की माँग ज्यादातर इसलिए बढ़ी है, क्योंकि बड़े राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक प्रशासनिक विकास कमजोर पड़ जाता है।" अधिकतर राजनीतिक विशेषज्ञों का मत भी यही है, कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही अलग राज्यों के निर्माण की माँग को पुख्ता करता है,1 भले ही इसके राजनीतिक कारण भी रहे है। पर बड़े राज्यों को विभाजित कर छोटे राज्य बना देने मात्र से ही सभी समस्याओं का (रामबाण) समाधान हो, ऐसा भी नही है।

उत्तराखण्ड की स्थिति :

पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के साथ–साथ सामरिक दृष्टि व अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण भी अलग है। नेपाल व तिब्बत (चीन) से अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें[2] जुडने के कारण न केवल यह क्षेत्र राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से, वरन् देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील है। राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सेनाओं एवं अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती है तथा अधिकतर युवावर्ग रोजगार के अभाव में पलायन के लिए मजबूर है। यही कारण है कि यहां के लोग 1952 से ही अपने लिए एक पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं।[3] लम्बे संघर्ष, त्याग, तपस्या, कुर्बानियों और 1994 के अभूतपूर्व जन–आंदोलन के बाद 9 नवम्बर 2000 को भारत के मानचित्र पर उत्तरांचल राज्य का उदय हुआ। जो 29 दिसम्बर, 2006 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद 1 जनवरी, 2007 को उत्तराखण्ड हो गया।[4]

आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों अलग–अलग धारणायें हैं, पर इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य निर्माण के इन 17 वर्षों में राज्य का विकास हुआ है पर किसी एक भाग के विकास को सम्पूर्ण राज्य का विकास मान लेना उचित एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है।

बार–बार सड़के, फ्लाई ओवर, यातायात के साधन, स्कूल, कालेज, अस्पताल, बिजली, पेयजल आदि सुविधायें बढ़ने की बात की जाती है, पर सच्चाई यह है कि राजधानी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी स्थाई राजधानी का मामला आज तक लटका पड़ा है, स्कूल बढ़े है फिर भी बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे है, अस्पताल बढ़े है पर सुविधाओं और डॉक्टरों का अभाव बना हुआ है, कालेज बढ़े है पर शिक्षक नही है, सड़के है पर लोग हिचकोल एवं धूल फांक रहे है, यातायात के साधन बढ़े है पर लोग जान जोखिम में डालकर टैक्सियों के छतों पर लटकते नजर आते है। पेयजल योजनायें बढ़ी है पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली की लाइनें बिछी है पर तार लटक रहे है, रोजगार बढ़ा है पर पलायन निरंतर जारी है। गोदामों में अनाज सड़ रहा हैं पर गरीब भूखे मरने के लिए विवश है। राज्य के दूरस्थ गाँव आज भी सुविधाओं के अभाव में जीने के लिए मजबूर है, क्या यही राज्य निर्माण का सपना था? तब यह कैसा विकास है जिससे गरीब के मूँह से रोटी दूर होती जा रही है, यह कैसा विकास है जिससे मानव का विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य के विकास का सही अर्थ सम्पूर्ण मानव जाति का एक समान विकास है जिसमें सभी को समानता के साथ अधिकारों की प्राप्ति हो, रोजगार मिले, जाति व समाज का सर्वांगीण विकास हो, गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अपराधीकरण, आदि बुराईयां समाज से दूर हो, जिससे लोगों में असन्तोष न बढे। लेकिन राज्य निर्माण के 17 वर्षों बाद भी संसाधनों की बात तो की जाती है पर इन संसाधनों को विकास से कैसे जोड़ा जाय इसके लिए आज तक भी कोई योजना नही है जिससे राज्य का विकास अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है।

राज्य के संसाधन :

राज्य के पास जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन, बागवानी एवं फलोत्पाद, जड़ी–बूटी आदि विभिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद है, जिनके बूते राज्य समृद्ध एवं विकसित होने की पूरी क्षमता रखता है। राज्य निर्माण के पूर्व भी जब संसाधनों की बात उठाई जाती थी तो बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री इन्ही संसाधनों की बात लगातार करते रहते थे और राज्य निर्माण के 17 वर्ष बाद भी यही बात दोहराई जा रही है। लेकिन आज तक ऐसी कोई नीति सामने नही आई जिसके बल पर विश्वास किया जा सके, कि वास्तव में ये संसाधन राज्य के विकास में सहायक है।

जल संसाधनः

मध्य हिमालय को जलस्तम्भ या वाटर टावर कहा जाता है और इन्हीं हिमनदों से सदानीरा गंगा और यमुना नदियां निकलती है। हिमालय की चोटियों पर पानी का अपार भण्डार बर्फ के रूप में जमा रहता है। यही से यह अपार भण्डार धीरे–धीरे पिघलकर नदियों को सालभर पानी देता है। इसके साथ ही इसमें नई बर्फ भी जमा होती रहती है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है और नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है।[5] नेपाल और भारत में पानी की अधिकांश आपूर्ति हिमालय से होती है। पेयजल और कृषि के लिए सिंचाई जल के अलावा देश में पनबिजली के उत्पादन में हिमालय से प्राप्त होने वाले पानी का बड़ा महत्व है।[6] लेकिन उत्तराखण्ड राज्य में विकास योजनाओं का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद उनके किनारे बसे गाँव, कस्बे तथा छोटे–बड़े शहर पानी के लिए तरस रहे है और सरकार केवल संसाधनों की बाते करती रहती है। जनकवि अतुल शर्मा की कविता; "विकास की कहानी, गाँव से दूर–दूर क्यों, नदी पास है, मगर ये पानी दूर–दूर क्यों।"[7] पहाड़ के दर्द और विकास योजनाओं की हकीकत वयां करने के लिए काफी है। एक सुसंगठित एवं व्यवस्थित प्रबंधन की कमी के कारण ये नदियां स्थानीय लोगों के लिए अनुपयोगी बनी हुई है। अतः उत्तराखण्ड के आत्मनिर्भर एवं समृद्धशाली राज्य होने के लिए वैज्ञानिक आधार पर परिस्थितियों के अनुकूल एवं पर्यावरण को ध्यान में रखकर ठोस नीतियों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिस पर ईमानदारी से कार्य करना होगा, तभी यहाँ की सदाबहार नदियां राज्य के विकास में कोई भूमिका निभा सकेंगी।

वन संसाधन :

वन सम्पदा को भी यहाँ के प्रमुख संसाधनों मे लिया जाता है जो कि सरकारी आंकडों के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 67 प्रतिशत है।[8] जबकि वास्तविकता यह है कि वन क्षेत्र इसके आधे से भी कम है। क्योंकि कुछ भूमि केवल वन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जबकि उसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है और न ही वन विभाग द्वारा वनीकरण का प्रयास किया जाता है (भले ही प्रतिवर्ष कागजों में हजारों हेक्टेअर भूमि में वनीकरण दिखाया जाता है)। कुछ भाग हिमालयी एवं चट्टानी होने के कारण उसमें कोई वनस्पति नही उगती है, कहीं लैन्टिना एवं काला बांसा जैसी खतरनाक झाड़ियों ने घेर दिया है जिसके साथ किसी भी प्रकार की घास एवं पेड़–पौधे नहीं पनप पाते है। इसके अतिरिक्त एक बडे भू–भाग को अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय पार्कों के रूप में आरक्षित किया गया है।9 ऐसा करना वृहद राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हित में, पर्यावरण संरक्षण तथा इस क्षेत्र की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए अनिवार्य है, परन्तु इस प्रकार राज्य की काफी भूमि आर्थिक रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त नही कही जा सकती है। वन भूमि का कुछ भाग राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव विहार तथा वायोस्फीयर के अधीन है। जिसके बदले भारत सरकार इस क्षेत्र को कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नही देती है। जबकि इसके बदले में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए, जिसके लिए उत्तराखण्ड सरकार को प्रयास भी करने चाहिए। चूँकि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण का मुद्दा क्षेत्रीयता का ही नही वरन् राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम स्थानीय विकास के कार्यों में बाधक न बने इस दृष्टि से भी सरकार को इसमें आवश्यक संशोधन करने चाहिए। ऐसे में वन उत्तराखण्ड राज्य को आर्थिक आधार दे पायेंगे यह तो हमारे प्रबंधन पर निर्भर करेंगा, किन्तु यदि वनों के विनाश की यही गति रही तो वन आर्थिक आधार दे पायें या न दे पायें, पर पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा अवश्य पैदा हो जायेगा।

पर्यटन :

राज्य में नैनीताल, कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, मसूरी, धनोल्टी, हर्षिल, नई टिहरी, जोशीमठ, चोपता, पौड़ी, कैम्टीफाल, गोविन्दघाट, फूलो की घाटी, गोपेश्वर, ग्वालदम, गैरसैण आदि पर्यटक स्थल विद्यमान है। इसके अलावा कई अनगिनत ऐसे स्थान भी है जिन्हें भविष्य में पर्यटक स्थलों के रुप में विकसित किया जा सकता है यह न केवल मौसमी पर्यटक स्थल होंगे वरन् वर्षभर पर्यटकों के आवागमन के केन्द्र बनकर राज्य की आमदनी का अच्छा साधन बन सकते है। जहाँ गर्मियों में पर्यटक मैदानों की लू भरी गर्मी, धूल, प्रदूषण, शोरगुल से निजात पाने एवं बच्चों को प्रकृति से परिचित कराने के लिए पहाड़ों में आते है वहीं शीत ऋतु में यहाँ हो रही बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अधिक से अधिक पर्यटक एवं सौन्दर्यप्रेमी आ सकते हैं, जिसका लाभ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सरकार एवं विभिन्न व्यवसायों जैसे; पर्यटन, यातायात, होटल, गाइड, पोर्टर आदि से जुड़े स्थानीय लोगों को मिलेगा। साहसी पर्यटन के रूप में पर्वतारोहण, ग्लाइडिंग, स्केटिंग, रीवर राफ्टिग, आइस हॉकी आदि खेलों के लिए हमारे पास विभिन्न नदियां एवं ग्लेशियर मौजूद है। औली जैसे सैकड़ों स्थल राज्य में मौजूद है जिन्हे शीतकालीन क्रीड़ा के लिए विकसित किया जा सकता है। यहाँ के दर्रे एवं पास ट्रेकिंग के लिए स्वर्ग है तो गंगा आदि नदियां जलक्रीड़ा के लिए देश विदेश के पर्यटकों का मनपंसद स्थान है। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड़, पार्क तथा सौन्दर्यकरण करके बोटिंग प्रतियोगिता जैसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित कर साहसिक पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में

प्रोत्साहित कर राज्य की आमदनी का अच्छा जरिया बनाया जा सकता है। परन्तु सच्चाई यह है कि सरकार आज भी चारधाम यात्रा तक सीमित है और पिछले 17 वर्षों में राज्य के लिए कोई ठोस पर्यटन नीति बनाई जा सकी है। इसलिए धरातलीय सच्चाई को स्वीकार करते हुए पर्यटकों को सभी प्रकार की उचित सुख–सुविधायें प्रदान करनी होंगी तथा अपने पारम्परिक खाद्यान्नों, वेशभूषा को बढावा देकर पर्यटकों को इसके प्रति आर्कषित करना होगा। इससे जहाँ एक ओर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर राज्य से हो रहे पलायन की गति पर भी विराम लग सकता है।

सब्जी एवं फलोत्पादन :

पहाड़ी इलाकों में अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन खेती लगातार खत्म होती जा रही है और अनाज का उत्पाद घटता जा रहा है, जिसका कारण राज्य के पास पर्याप्त साधन न होना भी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग कृषि एवं पशुपालन कार्य छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गये है तथा बचे–खुचे लोग मनेरगा के कार्य में व्यस्त हो गये है। बागवानी एवं फलोत्पादन से राज्य को विशेष लाभ हो सकता है पर उसे विकसित करने के कोई खास प्रयास अब तक नही किये गये है। फिर भी राज्य में फल एवं सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है लेकिन इनको बाजार तक पहुँचाने के लिए सड़कों का होना अत्यधिक महत्त्व रखता है, जिससे समय पर फलों एवं सब्जियों को बाजार तक पहुँचाया जा सके। यद्यपि कुछ स्थानों तक पहुँचने के लिए सड़के है, किन्तु वे बड़ी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा बरसात में कई–कई दिनों तक बद पड़ी रहती है जिसमें माल ले जाना तो दूर पैदल चलना भी असंभव हो जाता है। अतः दूरदराज के गाँवों को जब तक सड़कों या रज्जू मार्गों से नहीं जोड़ा जाता है तब तक विकास की बात करना बेमानी ही लगती है। भले ही प्राकृतिक आपदायें समस्याओं को बढाते है लेकिन इससे बढकर कई ऐसी समस्यायें है जो कि मानव द्वारा उत्पन्न की गई है जो कि कार्य, सभ्यता, ईमानदारी, कर्तव्य और समर्पण की कमी के कारण है। इसे इस बात से भी महसूस किया जा सकता है कि जब कोई वीआईपी किसी शहर के दौरे पर आते है तो टूटी–फूटी सड़कों की मरम्मत, सभी प्रकार के गढढों को भरकर एवं कूड़े–कचरे को रातोंरात हटाकर साफ कर दिया जाता है। प्रश्न उठता है कि यह कार्य पहले क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर किसी के पास नही है। यदि राजनेता औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखण्ड में पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर सकते है तो उन्हें वास्तविक रूपरेखा तैयार करके इस क्षेत्र में सुधार भी करने चाहिए जो कि विकास और रोजगार की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

चुनौतियां :

विकास की समस्या:

उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील भी है, इसकी अनदेखी न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से, बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है। बारूदी बिस्फोटों से सड़कें, भवन और सुरंग का निर्माण पहाड़ी जिलों के लिए विनाशक साबित होता जा रहा है पहाड़ छलनी होकर दरक रहे हैं जिस कारण लगातार बादल फटने, भूस्खलन की घटनायें आम बात हो गई हैं। राज्य आज आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य निर्माण के 17 वर्षों बाद भी राज्य के सुदूरवर्ती गाँव शासक प्रशासकों की उपेक्षा एवं अदूरदर्शिता के शिकार बने हुए हैं। क्षेत्र के विपुल संसाधनों के विकास, वन्य संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, पारम्परकि व्यवसायों के संरक्षण, कुटीर उद्योग धन्धों एवं औद्योगिकीकरण के माध्यम से विकास पर न तो अतीत में सोचा गया और नही वर्तमान में ध्यान दिया जा रहा है।

पलायन की समस्या :

आख्यों मां अंसधरि अंदिन, जब दयखदू छौ, कन खंगाल ह्वेन मेरा अच्छा भला गौं। यानि आँखों में आँसू आ जाते है जब देखता हूँ, कैसे खाली हुए मेरे अच्छे भले गाँव। कवि बृजमोहन कपटियाल की यह पंक्तियां सूबे में हो रहे पलायन का दर्द बयां करने को काफी है। पहाड़ के खेत, खलियान एवं गाँव के गाँव जहाँ पलायन के कारण खाली हो रहे है10 वहीं शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। राज्य निर्माण के बाद भी पलायन का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा, बल्कि अब हालात और भी खराब हो गये है खासतौर से पर्वतीय जिलों में। जिस पलायन के दंश और बच्चों के भविष्य की चिंता ने महिलाओं को पृथक पर्वतीय राज्य आंदोलन के लिए प्रेरित किया, वही दंश व पीड़ा आज महिलाओं को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है जिससे उनमें तीव्र गति से पलायन होने लगा है। आज पढ़ी–लिखी महिलायें हो या फिर अनपढ़, सभी अपना परिवार छोड़कर शहरों की ओर भाग रही है[11] प्रश्न आज भी बच्चों के भविष्य की चिंता का है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राज्य के सीमावर्ती गाँवों का खाली होना, किसी भी दशा में शुभ संकेत नही माना जा सकता। बावजूद सरकारी उपेक्षा को देखिए राज्य बने डेढ दशक से अधिक समय होने के बावजूद पलायन को रोकने की कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है।[12] यही नही 2013 में आई आपदा से उत्तराखण्ड में पलायन की गति को और भी बल मिला है। पहाड़ में आज भी यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि "पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के किसी काम नही आई।"

उपाय एवं सुझाव :

उत्तराखण्ड में विकास की रूपरेखा पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के अनुरूप होनी चाहिए। गाँवों को केन्द्र में रखकर विकास की नीति तैयार की जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। जबकि कृषि भूमि मात्र 13.5 प्रतिशत है[13] उसमें भी अधिकांश भूमि असिंचित एवं उखड़ है। इसलिए राज्य में विकास का मानक ग्रामीण विकास होना चाहिए। नये राज्य में विकास की किरण राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचे इसके लिए विशेष प्रयास और नीति बनाई जानी चाहिए। नदियों के किनारे बसे गाँव, शहर, कस्बे पानी के लिए तरस रहे है उन तक पानी पहुँचाने की नीति होनी चाहिए। नीतियां पाईप लाइन बिछाने की नही वरन् पाईपों लाइनों में पानी पहुँचाने की होनी चाहिए। वस्तुतः छोटे राज्यों का निर्माण ही विकास का मानक नही है बल्कि समर्पित एवं ईमानदार नेतृत्व, राज्य की संभावित आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्रीय परिस्थितियों एंव पर्यावरण संवत योजनायें, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग एंव विदोहन वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। सीनीय जल सम्पदा की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए लघु विद्युत उत्पादन को राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में विकसित करना होगा। लेकिन इसके लिए वस्तुपरक अध्ययन कराने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लग सके। जड़ी–बूटी आधारित उद्योगों के माध्यम से क्षेत्र के विकास और आर्थिक संसाधन जुटाने के विषय में गम्भीरता से चिंतन की आवश्यकता है। भारी उद्योग स्थानीय पर्यावरण को हानि पहुँचा सकते है ऐसे में वनाधारित लीसा, कत्था, टोकरी बुनना, शहद, काफल, बुरांस, मौसमी, संतरे का जूस, आँवला, आम का अचार, तिमला, बेडू, तल्ड़, बेवरू, गेंठी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि को बढावा देने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए।

अतः राज्य निर्माण के बाद लोग इन्हीं स्थितियों की पुनरावृत्ति के बजाय दूरदराज गाँवों में चलने लायक सड़कें, पर्यावरण की दृष्टि से रज्जू मार्ग, संचार की अच्छी सुविधायें, गाँवों में युवाओं के लिए रोजगार, पलायन पर रोक, आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बाजार, बिना बाधा के पानी और बिजली, प्रभावकारी स्वास्थ्य तंत्र, बच्चों के लिए अच्छी शैक्षणिक सुविधायें चाहते है, जिसके लिए यहाँ के जनमानस ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास समान रूप से चलते रहें ऐसी योजनाओं का निर्माण करने की नितांत जरूरत है। परम्परागत कृषि

व्यवस्था को नई तकनीकी से जोड़कर नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पलायन की समस्या को रोकने के लिए रोजगार के साधन एवं पर्यटन नीति घोषित की जानी चाहिए। बाहरी लोगों के द्वारा भूमि खरीद–फरोख्त पर प्रतिबंध तथा आम आदमी तक विकास की किरण पहुंच सके इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए तभी सामरिक एवं सीमांत राज्य उत्तराखण्ड विकास की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्र की दृष्टि से हितकर होगा तभी पृथक राज्य जनता के स्वप्नों का राज्य बन पायेगा।

संदर्भ:

1.Hardwari Lal : Politics is all, The Hindustan Times, January 4, 1997
2.बी. आर. पन्त; 1993: उत्तराखंड का प्राकृतिक आधार, धाद, भाग–1, देहरादून, पृष्ठ–58
3. अजय कुमार: उत्तराखंड की माँग: गेंद अब इकां के पाले में, माया 15 सितम्बर, 1991, पृष्ठ–29
4.भट्ट, त्रिलोक चन्द्र; 2008: उत्तराखण्ड: राज्य आंदोलन का नवीन इतिहास, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–404
5.रावत, जयसिंह; 2013: हिमालयी राज्य सन्दर्भ कोष, विन्सर पब्लिशिंग कं0, देहरादून, पृष्ठ–14
6.रावत, जयसिंह; 2013: उपरोक्त, पृष्ठ–9
7.यनू उत्तराख्ण्ड चयेणू छ, मनीष ओली; हिन्दुस्तान, 9 नवम्बर, 2009, पृष्ठ–9।
8. दलीपसिंह; 1999: उत्तराखण्ड राज्य की आवश्यकता, औचित्य एवं वास्तविकता का एक अध्ययन, हे.नं.ब. ग.वि.वि., श्रीनगर (गढ़वाल)
9.Negi, S. S.; 1994 : Garhwal: The Land And People, Indus Publication, New Delhi, P. 113.117
10. केदार दत्त; पलायन हालात के गवाह, दैनिक जागरण देहरादून, 7 नवम्वर, 2012, पृष्ठ–14।
11.कमला पंत; हिन्दुस्तान, 9 नवम्वर, 2009 पृष्ठ–3।
12.संदर्भ संख्या–9, केदार दत्त; पलायन हालात के गवाह, दैनिक जागरण देहरादून, 7 नवम्वर, 2012, पृष्ठ–14।
13.उनियाल, द्वारिका प्रसाद, 1995 : हिमालय टाइम्स– उत्तराखंड का दस्तावेज, कौशिक समिति की रिपोर्ट, शिमला, पृष्ठ–64

डॉ. दलीपसिंह
राजनीति विज्ञान विभाग , असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ,राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी (नैखरी) पो. ऑ.–जामणीखाल .

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org